

पीएम गति शक्ति

वर्तमान संदर्भ



सरकार, गति शक्ति- नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्स, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (production-linked incentive) स्कीम के लाभार्थियों, मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान (mega integrated textile region and apparel-MITRA) पार्को और देश भर में उचित मूल्य की दुकानों को मैप करने की योजना बना रही है।



KHAN SIR

Follow Us: [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) [@](#) [@khanglobalstudies](#)



पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में

गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफार्म है। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकिकृत योजना और समन्वित कार्यन्वयन के लिए रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ता है।

1

यह समन्वित और एकीकृत योजना, परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन, रसद व्यवस्था और कुशल परिवहन प्रणालियों के अनुकूलन की सुविधा के लिए भौगोलिक विशेषताओं, भूमि रिकॉर्ड आदि सहित विभिन्न डेटा परतों के निर्माण पर निर्भर करता है।

2

इस योजना के अंतर्गत अलग से कोई धन आबंटित नहीं की गई है। स्वीकृत परियोजना लागतों के अन्दर परियोजना आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को बजट आबंटित किया जाता है।

3

पीएम गति शक्ति के 6 स्तंभ





महत्त्व

01

आर्थिक विकास : यह आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है और सात इंजनों, अर्थात् सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के द्वारा संचालित है। योजना के दायरे में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता के लिए सात इंजन शामिल हैं।

02

बुनियादी ढांचा योजनाएं : इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं जैसे- भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क / भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि शामिल हैं।

03

मंत्रालयों के बीच समन्वय : यह रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को एक साथ लाता है।

04

रोजगार सृजन : यह अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

05

निवेश के अवसर : यह पहल निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए अच्छा अवसर प्रदान करता है, जिसका अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।



चुनौतियां

भूमि अधिग्रहण :

भूमि अधिग्रहण में संरचनात्मक समस्याएं हैं। परियोजना कार्यान्वयन की दर बहुत कम है जो मिशन की लागत को बढ़ा सकती है।

01

पर्यावरण मंजूरी :

पीएम गति शक्ति परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मंत्रिस्तरीय समूह का प्रस्ताव, देश के पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के मूल्यांकन और आकलन की गुणवत्ता से समझौता कर सकता है।

02

नौकरशाही में देरी:

नौकरशाही लालफीताशाही के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय से हो पाना संदेहपूर्ण है।

03

आगे की राह

इस योजना में, सभी मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को एक ही मंच पर **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे** के साथ मैप किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों के अलग-अलग परियोजनाओं की जांच की जाएगी और भविष्य में समग्र योजना के मापदंडों के भीतर उन्हें मंजूरी दी जाएगी, जिससे प्रयासों का तादात्म्यकरण होगा। यह भारत में एक विश्व स्तरीय, निर्बाध मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क बनाने के लिए सुगमता स्थापित करेगा।

PM GATI SHAKTI

Current Context



The government plans to map startup incubators, beneficiaries of the production-linked incentive (PLI) schemes, mega integrated textile region and apparel (MITRA) parks, and fair price shops across the country, through the Gati Shakti-National Master Plan.





About PM Gati Shakti-the National Master Plan

The PM Gati Shakti-National Master Plan for Multi-modal Connectivity is a digital platform to bring 16 Ministries, including Railways and Roadways, together for integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity projects by breaking the departmental silos.

1

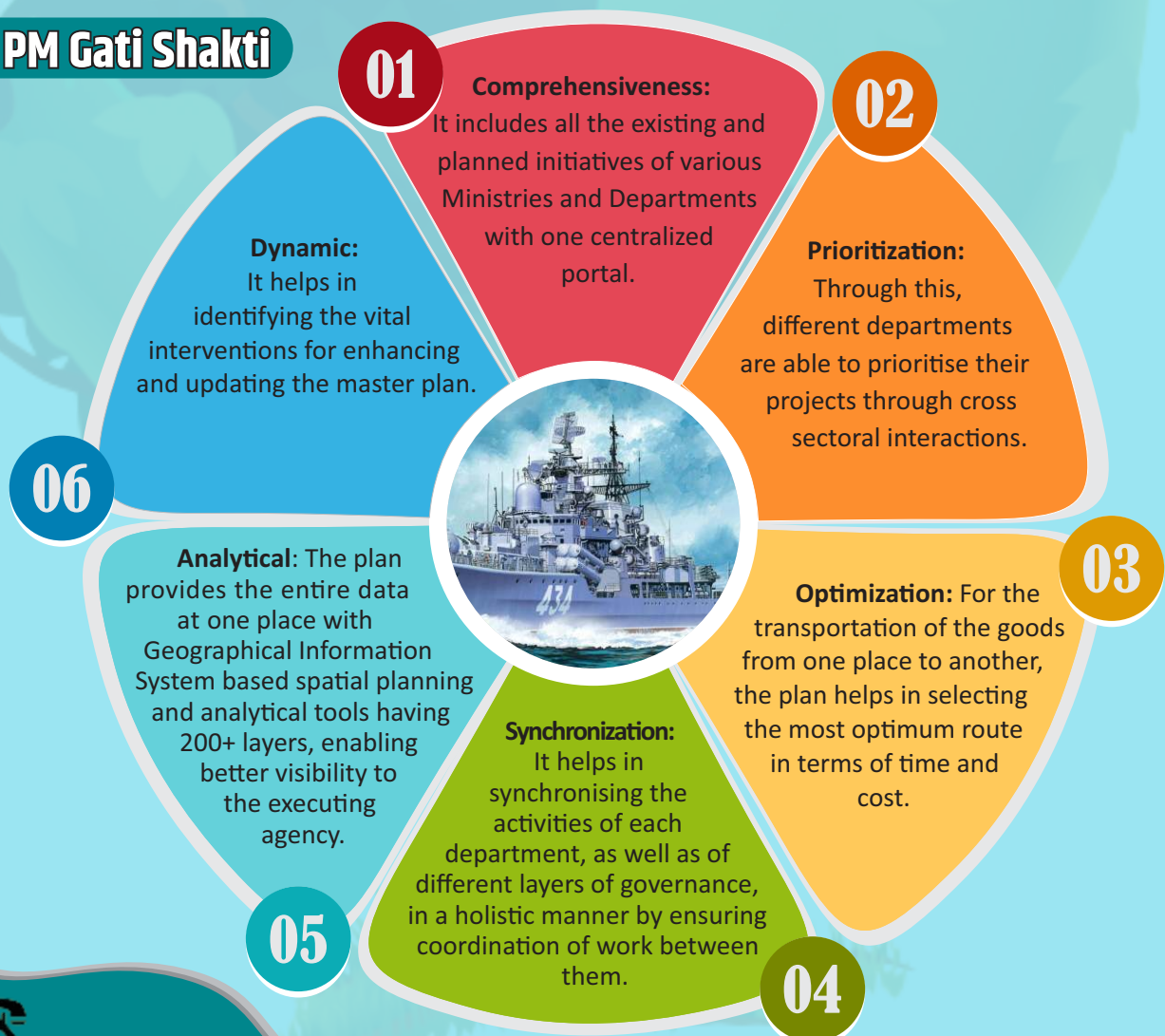
It relies on creation of various data layers including geographical features, land records, etc., to facilitate coordinated and integrated planning, project preparations and implementations, optimization of logistics arrangements and efficient transportation systems.

2

There are no separate funds allocated under this Plan. The budget is allocated National Highways projects wise, as per project requirements, within the sanctioned project costs.

3

6 Pillars of PM Gati Shakti





Significance

01

Economic growth: It is a transformative approach for economic growth and sustainable development and is driven by seven engines, namely, Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways, and Logistics Infrastructure. The scope of the plan encompasses the seven engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency.

02

Infrastructure schemes: It incorporates the infrastructure schemes of various Ministries and State Governments like Bharatmala, Sagarmala, inland waterways, dry/land ports, UDAN etc.

03

Coordination between Ministries: It brings 16 Ministries including Railways and Roadways together for integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity projects.

04

Job creation: It leads to huge job opportunity in infrastructure and construction sector which cater semi-skilled and unskilled workers.

05

Investment opportunity: This initiative provides a virtuous cycle of private and public investment which will have a multiplier impact on the economy, commerce and industry.



Challenges

Land acquisition: There are structural problems in land acquisition. The rate of project implementation is very low which may increase the cost of the mission.

01

Environmental clearance: The Ministerial Group's proposal for quicker green nods for PM Gati Shakti projects could compromise the quality of appraisals and assessments in ecologically vulnerable regions of the country.

02

Bureaucratic delay: There are still doubt on timely implementation of the projects due to bureaucratic red-tapism.

03

Way Forward

In this plan, all the existing and proposed economic zones have been mapped along with the multi-modal connectivity infrastructure in a single platform. Individual projects of different line Ministries would be examined and sanctioned in future within the parameters of the overall Plan, leading to synchronization of efforts. It will bring synergy to create a world class, seamless multi-modal transport network in India.